में कमी लाना, मांग प्रबंधन तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन, अधिशेष वाले राज्यों से कमी वाले राज्य को ऊर्जा अन्तरण आदि जैसे उपाय सम्मिलित हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र में (हरियाणा में 988 मे०वा० समेत) 9849.3 मे०वा० नव उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है।

(ग) निजी क्षेत्र में यमुना नगर ताप विद्युत परियोजना के निष्पादनार्थ एक प्रस्ताव की ओर अभी ध्यान दिया जा रहा है। एनटीपीसी द्वारा 400 मे०वा० फरीदाबाद गैस परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है तथा गैस लिकेज की जानी है।

(घ) 8 और 9 जनवरी, 1993 को हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में एक कार्ययोजना अपनाई गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि 31 मार्च, 1993 से पूर्व कृषि टैरिफ को 50 पैसे प्रति यूनिट संशोधित किया जाए। राज्यों से यथा-प्राप्त उन राज्यों के नामों की सूची दर्शाने वाला विवरण जिन्होंने कृषि टैरिफ 50 पैसे प्रति यूनिट संशोधित की है, संलग्न है।

विवरण

राज्य और संघ शासित क्षेत्र जिनकी संशोधित कृषि टैरिफ 50 पैसे कि०वा० आवर है

1. उड़ीसा
2. मध्य प्रदेश
3. राजस्थान
4. हरियाणा
5. मिजोरम
6. गुजरात
7. दिल्ली
8. महाराष्ट्र
9. पंजाब
10. मेघालय
11. असम
12. त्रिपुरा
13. पश्चिम बंगाल
14. संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार

Thermal Power Station at Hissar

149. SHRI S. S. SURJEWALA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether NTPC is setting up a 1000 MW Thermal Power Station at Hissar in Haryana, if so, the details thereof;

(b) whether the Ministry of Power has cleared the above plant;

(c) whether the various clearances such as coal linkage, rail linkage, etc. have been approved for this plant;

(d) whether the Planning Commission has given clearance for the necessary funds for the construction of this plant;

(e) whether the Ministry has received a number of proposals for setting up of Thermal Plants by the Haryana State Electricity Board; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) (a) The National Thermal Power Corporation (NTPC) has no proposal to set up a thermal power station at Hissar in Haryana.

(b) to (d) Do not arise.

(e) and (f) No proposal for setting up of Thermal Power Plants by the Haryana State Electricity Board is with the Central Electricity Authority.

गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों के विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव

150. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव क्या हैं और साथ ही उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की मंजूरी दिए जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दी जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) से (ग) ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3
महाराष्ट्र		
1	भीवपुरी पम्पित संचयन स्कीम (90 मे०वा०)	हालांकि यह स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई, 91 में तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त पाई गई थी, फिर भी कृष्णा नदी के जल के पश्चिम में विपथन के सम्बन्ध में महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के मध्य एक समझौते के अभाव में इसे स्वीकृत नहीं किया गया है।
2	निकालधारा पम्पित संचयन स्कीम (4×100 मे०वा०)	यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु भेजी गई है।
3	डभोल के निकट बार्ज माउंटेड विद्युत संयंत्र 100 मे०वा०	
4	डभोल सीसीजीटी (2015 मे०वा०)	महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए यह प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं। डभोल तथा खापरखेड़ा परियोजनाओं को कुछ शर्तों के आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा "सैद्धान्तिक रूप में" स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
5	खापरखेड़ा टीपीएस (2×210 मे०वा० यूनिट 5 तथा 6)	
6.	भुसावल (बी) टीपीएस (2×500 मे०वा०)	यह स्कीम तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई है।

Accord between NTPC and States for Bulk Supply of Power

151. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Thermal Power Corporation has signed an accord with a few States for facilitating bulik power supply to such States; and

(b) if so, what are the names of such States and what will be their respective share of power supply?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) The National Thermal Power Corporation (NTPC) has signed Bulk Power Supply Agreements with the State Electricity Boards of West Bengal, Orissa, Bihar, Haryana, Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and State Governments of Sikkim, Jammu & Kashmir, Goa, and Union Territory Administrations of Chandigarh, Pondicherry, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Damodar Valley Corporation and Delhi Electric Supply Undertaking.

The allocation of power to various beneficiaries from NTPC's stations is shown, station-wise, in the Statement.